

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,वर्ष 22,अंक - 111- शुक्रवार 20- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,इक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

डीपफेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे : पीएम मोदी

एआई समिट में अंबानी ने कहा...डेटा की तरह सस्ता होगा एआई,10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे

नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 'इंडिया एआई इमैक्ट समिट 2026' के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर 'न्यूट्रिशन लेबल' होता है,वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी 'ऑथेंटिसिटी लेबल' होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। वहीं, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को 'इंटेलिजेंस युग' में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा एलान किया है। समिट को आज नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के CEO सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे लीडर्स ने संबोधित किया। 16 फरवरी से शुरू समिट 20 फरवरी तक चलेगी।

एआई में भय नहीं 'भाग्य' और भविष्य

पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे अपने 'भाग्य' और उज्ज्वल भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है।

कंटेंट पर 'ऑथेंटिसिटी लेबल' की जरूरत : मोदी

पीएम ने सुझाव दिया कि जैसे खाने के सामान पर 'न्यूट्रिशन लेबल' होता है, वैसे ही डिजिटल

एआई को 'ओपन सोर्स' बनाएं : मोदी

पीएम मोदी ने कहा भारत ने दुनिया की 'कॉन्फिडेंशियल' सोच से अलग हटकर एआई कोड को 'ओपन शेर' करने की बात कही। पीएम का मानना है कि जब तकनीक सबके लिए खुली होगी, तभी दुनिया भर के युवा दिमाग उसे बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे।

इमून-सैट्रिक अप्रोच और नौकरियां : मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे युग में हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर क्रिएट करेंगे। उन्होंने स्किलिंग और रिस्किलिंग को एक 'मास मूवमेंट' बनाने पर जोर दिया।

अंबानी बोले- डेटा की तरह सस्ता होगा एआई

रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जिस तरह जियो ने देश में डेटा सस्ता किया, उसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आम भारतीय तक किफायती दरों पर पहुंचाया जाएगा। इस दिशा में जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले सात साल में 710 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। एआई से पैदा होने वाली चिंताओं पर अंबानी ने कहा कि एआई वह मंत्र है जो हर यंत्र को तेज, बेहतर और स्मार्ट तरीके से काम करने की शक्ति देता है। मैं एआई को आधुनिक अक्षय पात्र के रूप में देखता हूँ, जो अंतहीन पोषण प्रदान कर सकता है। एआई नौकरियां नहीं छीनेगा बल्कि, यह हाई-स्किल काम के नए मौके पैदा करेगा।

देश का पहला 'नेक्स्ट जनरेशन' डेटा सेंटर बनाएगा टाटा ग्रुप

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप अगली पीढ़ी की एआई ट्रेनिंग और इंफ्रेंस के लिए खास तौर पर तैयार भारत का पहला लार्ज-स्कैल 'एआई-ऑप्टिमाइज्ड' डेटा सेंटर बना रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इसकी पहली 100 मेगावाट क्षमता बनाने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की है,जिसे आगे चलकर एक गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा।

कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए। इससे और क्या एआई द्वारा बनाया गया लोगों को पता चल सकेगा कि क्या असली है (फैक्टिकेटेड) है।



सुंदर पिचाई बोले...अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा एआई

गूगल भारत में अपने 15 बिलियन डॉलर (1.35 लाख करोड़ रुपए) के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के हिस्से के रूप में एक 'फ्लू स्टैक एआई हब' स्थापित कर रहा है। इस हब में गीगावाट स्केल की कंप्यूटिंग और एक नया इंटरनेशनल सब-सी केबल गेटवे होगा। हर किसी के लिए उपयोगी एआई बनाने के लिए हम साहसिक कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है और सबसे कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। हमें उन क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उतना ही साहसी होना चाहिए जहां अब तक तकनीक की पहुंच नहीं थी।

नेमलेट पर 'भारत': जी-20 के बाद फिर दिखा वही संदेश

समिट के प्लेनरी सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर बैठे, तो उनके सामने रखी टेबल पर देश के नाम की नेमलेट पर 'भारत' लिखा हुआ था। यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम 'भारत' इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले 2024 में दिल्ली में हुए जी-20 समिट में भी पीएम की नेमलेट पर 'भारत' लिखा था। उस समय राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए न्योता पत्र में भी 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया था, जिस पर काफी चर्चा हुई थी।

ओपनएआई और एंथ्रोपिक

ने गुप फोटो में नहीं पकड़ हस

एआई कंपनी ओपनएआई और एंथ्रोपिक के बीच की कॉम्पिटिशन एक बार फिर चर्चा में है। आज इंडिया एआई इमैक्ट समिट के दौरान एक ग्रुप फोटो ली जा रही थी। इस दौरान ओपनएआई के सीओओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के को-फाउंडर डारियो अमोदेई एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़।

भाजपा सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय 'चार्यशीट' जारी : प्रियंका गांधी



नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने गुरुवार को असम में भाजपा-नीत सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय 'चार्यशीट' जारी करते हुए उस पर भ्रष्टाचार,अधूरे वादों और अल्पसंख्यकों के बीच भय का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले गुवाहाटी में इस दस्तावेज का अनावरण किया गया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर समाज के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न की है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रही है। पार्टी के अनुसार छह स्वदेशी सज्जदों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने तथा चाय बागान

श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 351 रुपये करने का आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके करीबी सहयोगियों और मंत्रियों के परिजनों के साथ मिलकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है। भाजपा ने पूर्व में ऐसे आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।

असम चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन समिति की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड़ा दो दिवसीय दौरे पर राज्य में हैं और पार्टी के चुनाव अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से जारी यह 'चार्यशीट' आगामी चुनावों में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

दिल्ली-हरियाणा समेत इन 22 राज्यों में होगा एसआईआर चुनाव आयोग बोला- अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी...

नई दिल्ली, 19 फरवरी 2026। देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाली है। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। आयोग के सचिव पवन दीवान का कहना है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चिठ्ठी लिखी गई है, जिसमें जल्द से जल्द एसआईआर से जुड़ी तैयारियों को पूरा करने को कहा गया है। आयोग ने अपने लेटर में कहा कि दिल्ली, कर्नाटक समेत बचे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया इसी साल अप्रैल से शुरू करने की उम्मीद जताई है। उसमें आगे बताया गया है कि 24 जून, 2025 को चुनाव आयोग ने आदेश में कहा था कि देशभर में यह प्रक्रिया करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई थी। यहां पर काम पूरा होने के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर, 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं सूची को अपडेट किया जा रहा है। साथ ही



अब इन राज्यों में कराई जाएगी एसआईआर

एसआईआर प्रक्रिया के लिए, जो राज्य छूट गए थे। इसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। इस राज्यों में यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है।

नए वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं और लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों में सुधार किया जा रहा है।

एसआईआर के लिए आयोग ने ये दस्तावेज किए मान्य

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता अपने बीएलओ/बीएलए को पहचान के तौर पर मान्य किए गए 12 दस्तावेजों में से एक कोई भी दे सकते हैं। जिसमें मतदाता का पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड को शामिल किया गया है।

केंद्र ने पंजाब में 6 लेन के सड़क प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। पंजाब में बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एनएच-205ए के अंबाला-चंडीगढ़ सेक्शन को जीएफपीए बाइपास से जोड़ने के लिए 6-लेन वाले एक्सप्रेस-कटोल्ड ग्रीनफील्ड स्तर के निर्माण करने की घोषणा की है। इसके लिए 1,463.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। नितिन गडकरी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि यह परियोजना ट्राइसिटी रिंग रोड का हिस्सा है। इससे मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला के प्रमुख शहरी जंक्शनों पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और भारी वाहनों का आवागमन डायवर्ट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से एनएच-44, एनएच-205ए और एनएच-152 पर जाम की समस्या कम होगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश, विशेषकर शिमला क्षेत्र की ओर तेज और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रा समय घटेगा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूती मिलेगी।



जातिवाद से ऊपर उठकर 'भारतवासी' होने पर करें गर्व : आनंदीबेन पटेल

सूरत,19 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से जाति के दायरों से बाहर निकलकर 'भारतवासी' और 'हिंदुस्तानी' होने पर गर्व करने की अपील की। उनके अनुसार सच्चा नेतृत्व वही है जो पूरे समाज को साथ लेकर चले, न कि किसी एक उपजाति तक सीमित रहे। आनंदीबेन पटेल गुरुवार को सूरत में आयोजित 'क्राफ्ट रुट' कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। यह कार्यक्रम हर वर्ष उनकी पुत्री अनार पटेल द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में पुराने समय को याद करते हुए आनंदीबेन ने कहा कि पहले गांव में यदि केवल दो-तीन पटेल परिवार भी होते थे,तो किसी भी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी पूरा गांव,विशेषकर पटेल परिवार मिलकर निभाते थे।



सुप्रीम कोर्ट ने पति को लगाई फटकार..छह महीने के जुड़वां बच्चों को मां से अलग करना सबसे बड़ी कूरता

नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वैवाहिक विवाद में अलग हुए पति द्वारा छह महीने की उम्र में जुड़वां बच्चों को उनकी मां से अलग करने के मामले को 'सर्वोच्च कूरता' का मामला करार दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ,संदीप मेहता और एनवी अंजारी की पीठ ने डेढ़ साल के बच्चों को मां से अलग करने के लिए पति को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अलग रह रहे पति-पत्नी को अगली सुनवाई की तारीख पर अपने बच्चों के साथ न्यायाधीशों के समक्ष कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया। पीठ ने टिप्पणी की,'पति ने महज छह महीने के बच्चों को उनकी मां से अलग करके घोर कूरता की है। बच्चों की भलाई सबसे पहले है। यह न्याय का घोर अपमान है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह महीने के छोटे बच्चों



को उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। यह घोर कूरता है। सुप्रीम कोर्ट अलग रह रहे पति की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पत्नी की ओर से लखनऊ में शुरू किए गए वैवाहिक मामलों को पंजाब में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पति के वकील ने कहा कि अदालत को जुड़वां बच्चों के संबंध में

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी

कांग्रेस ने करणी सेना के कार्यकर्ता का

वीडियो शेयर किया,आरोपी कोटा से पकड़ाया

नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को यह दावा किया। उन्होंने धमकी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। पवन खेड़ा ने लिखा कि पूरा आरएसएस-भाजपा तंत्र एक 'गोडसे फैक्ट्री' है। तथाकथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और '25 सांसदों' के खिलाफ दी गई

धमकी कोई अलग-थलग पड़ौ घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। उन्होंने एक्स पर लिखा-कट्टरपंथ ऐसे ही काम करता है। वे पहले एक झूठ बनाते हैं, पॉलिटिकल अर्थोरीटी उसे आगे बढ़ाती हैं और तब तक फैलाती हैं जब तक उनके फॉलोअर्स के मन में नफरत और हिंसा नहीं पर जाती। तब भी गोडसे बनाया गया था। आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है।

रक्षा मंत्री ने विशाखापतनम में अभ्यास मिलन का उद्घाटन करते हुए समुद्री क्षेत्र की

उभरती चुनौतियों से निपटने में वैश्विक समुदाय की एकजुटता का आह्वान किया

नई दिल्ली,19 फरवरी 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पारस्परिक सम्मान और सहयोग भावना से समुद्र की उभरती जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापतनम में आयोजित अभ्यास मिलन के उद्घाटन समारोह में 74 देशों के नौसेना प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतराष्ट्रीय शांति स्थापना में नौसेनाओं की भूमिका समय के साथ बढ़ रही है। साथ ही, पिछले कुछ दशक में आर्थिक विकास में काफी वृद्धि हुई है, जिससे अंतराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन में भी बहुत



वृद्धि हुई है। इससे जलडमरूमध्य और जलमार्गों पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जिससे कई बार संघर्ष की आशंका उत्पन्न होती है। समुद्री संसाधनों, विशेष रूप से दुर्लभ खनिजों

पर बढ़ते अंतराष्ट्रीय ध्यान से इस तनाव में एक नया पहलू जुड़ गया है। इसके अलावा, हमें अपने जलक्षेत्रों को आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अपना जाल फैला रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पारंपरिक खतरों के साथ ही समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध रूप से मछली पकड़ने, तस्करी, साइबर सुरक्षा में खामियां और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान जैसी उभरती चुनौतियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ा रहा है, जिससे मानवीय और आपदा राहत अभियान बार-बार करने पड़ रहे हैं और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।



है। जब कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में लौटता है, तो यही पैराशूट उसकी तेज गति को कम करने में मदद करता है। यह टेस्ट बुधवारको चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा में किया गया। यह डायनेमिक टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की स्पेशल हाई-स्पीड एयरोडायनेमिक और बैलिस्टिक मूल्यांकन सुविधा RTRS में पूरा हुआ।

कोरिया प्रवास में 'कमरे' की राजनीति...देर रात मंत्रियों के स्टाफ में तकरार, सुबह माफी से शांत हुआ मामला?

फोटो सेशन में व्यस्त रहा प्रशासन,विश्राम गृह में भड़की बहस: किस मंत्री की नाराजगी से मची हलचल?

- मंच पर विकास,पीछे विवाद: वन विश्राम गृह में मंत्रियों के कर्मचारियों की भिड़ंत से गरमाया माहौल
- प्रोटोकॉल बनाम प्रतिष्ठा:मुख्यमंत्री दौरे के दौरान कमरे को लेकर विवाद की चर्चा तेज
- कोरिया दौरा: स्वागत से ज्यादा 'सेल्फी' पर ध्यान,समन्वय की चूक से बढ़ी देर रात की तनावनी

-वि सिंह-
बैकुंठपुर, 19 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

विष्णु देव साय का कोरिया जिले में दो दिवसीय प्रवास विकास घोषणाओं और लोकार्पण-शिलान्यास के लिए याद किया जाएगा,लेकिन परदे के पीछे की एक घटना ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं,मंच पर मुस्कानें थीं,प्रेस नोट में उपलब्धियों की लंबी सूची थी,पर देर रात वन विभाग विश्राम गृह के गलियारों में 'कमरे' को लेकर उठा विवाद अब चर्चा का विषय बना हुआ है,आधिकारिक पुष्टि भले न हो, पर सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं,वे एक अलग तस्वीर पेश करती हैं।

महीने भर की कसरत, दो दिनों की भागदौड़

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने लगभग पूरे महीने तैयारियों में जुटकर व्यवस्थाओं का खाका खींचा-हेलीपैड से लेकर ओपन थियेटर तक,स्वागत द्वार से लेकर भोजन-व्यवस्था तक,अधिकारियों की बैठकों का दौर चला,विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं,और प्रोटोकॉल की फाइलें बार-बार दुरुस्त की गईं,दौरा संपन्न हुआ,घोषणाएं हुईं,और जैसे ही 'उड़ान खटोला' ने उड़ान भरी, प्रशासन ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी राहत के बीच एक ऐसी घटना की चर्चा शुरू हुई, जिसने पूरी 'सफलता' पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।

देर रात की तकरार: 'आवंटन' बनाम 'अधिकार'

सूत्रों के अनुसार 16-17 फरवरी की दर्यानी रात जिला मुख्यालय के एकांत में स्थित वन विभाग विश्राम गृह में दो वरिष्ठ मंत्रियों के स्टाफ के बीच तीखी बहस हुई, बताया जाता है कि एक मंत्री का आगमन अपेक्षित विलंब से हुआ,जबकि दूसरे मंत्री के कर्मचारी पहले से आवंटित कमरे में पहुंच चुके थे, जब देर रात कमरे के आवंटन पर चर्चा हुई,तो बातों का सिलसिला तेज हो गया-कौन-सा कमरा 'वरिष्ठ' है, किसने प्राथमिकता मिलनी चाहिए,और लिखित आवंटन क्या कहता है? बहस बढ़ी और कथित तौर पर आवाजें भी ऊंची हुईं,यहां प्रश्न उठता है-यदि आवास-आवंटन स्पष्ट और पूर्व-निर्धारित था,तो विवाद की नौबत क्यों आई? क्या समन्वय में कमी थी,या सूचना समय पर संबंधित पक्षों तक नहीं पहुंची?

लाइजनिंग स्टाफ: 'लिसनिंग' से ज्यादा 'पोजिंग'?

इस प्रकरण में लाइजनिंग स्टाफ की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं,जिन कर्मचारियों को अतिथियों के स्वागत,आवास-व्यवस्था और

कार्टवाई की आहट: क्या केवल लाइजनिंग स्टाफ ही बनेगा बलि का बकरा ?

विष्णु देव साय के कोरिया प्रवास के दौरान विश्राम गृह में कथित विवाद के बाद अब प्रशासनिक हलकों में कार्टवाई की चर्चा तेज है, सूत्रों के अनुसार लाइजनिंग कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्टवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है-क्या पूरा दोष केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर डालकर मामला समाप्त कर दिया जाएगा, या जिम्मेदारी तय करने का दायरा अधिकारियों तक भी पहुंचेगा? वन विभाग विश्राम गृह में यदि वास्तव में मंत्रियों की आवास-व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति बनी और मामला बहस तक पहुंचा, तो यह केवल एक कर्मचारी की चूक नहीं मानी जा सकती, मंत्रियों के ठहराव, कक्ष-आवंटन और प्रोटोकॉल की अंतिम जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है,लाइजनिंग स्टाफ निर्देशों का पालन करता है, नीति तय नहीं करता, ऐसे में यदि समन्वय में कमी रही, तो जवाबदेही तय करते समय आदेश देने वालों और निगरानी करने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, प्रशासन के लिए यह आसान विकल्प हो सकता है कि 'कार्टवाई' का संदेश देने के लिए छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाए, लेकिन यदि निर्णय-श्रृंखला की पूरी कड़ी की समीक्षा नहीं हुई, तो यह केवल औपचारिक कार्टवाई बनकर रह जाएगी।

अधिकारियों की फोटोग्राफी पर उठे सवाल

दौरे के दौरान एक और चर्चा ने जोर पकड़ा-अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें, कार्यक्रमों के दौरान कई अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ फोटो-फ्रेम में दिखे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी सामने आईं, आलोचकों का कहना है कि जब कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मुख्यमंत्री से सीधे संवाद न हो पाने को लेकर असंतोष जता रहे थे, तब अधिकारियों की लगातार फोटो उपस्थिति ने असहजता बढ़ाई, यह प्रश्न स्वाभाविक है-क्या किसी अधिकारी का आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मंचीय या व्यक्तिगत फोटोग्राफी में अत्यधिक सक्रिय दिखना प्रशासनिक शिष्टाचार के अनुरूप है? क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि प्राथमिकता जनसंपर्क से ज्यादा 'छवि-संपर्क' को दी जा रही है?

समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे कथित तौर पर कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफी और सोशल मीडिया अपडेट में व्यस्त दिखाई दिए, सूत्रों का कहना है कि कई कर्मचारी पल-पल की तस्वीरें साझा कर रहे थे-मुख्यमंत्री के साथ,मंच के साथ,स्वागत के साथ, लेकिन जब देर रात कमरे को लेकर समन्वय की आवश्यकता पड़ी, तो संबंधित अधिकारी मौके पर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, यदि यह सही है,तो यह प्रशासनिक प्राथमिकताओं का विचलन है-जहां कर्तव्य की जगह कैमरा केंद्र में आ गया।

अधिकारी वर्ग की व्यस्तता: फोटो-फ्रेम बनाम दायित्व

जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाने में विशेष रुचि लेते दिखे-ऐसा सूत्रों का दावा है, कार्यक्रम के दौरान जब-जब अवसर मिला, फोटो-फ्रेम में शामिल होने की होड़ रही, आलोचना यह है कि अन्य मंत्रियों के ठहराव और आपसी समन्वय की जिम्मेदारी अपेक्षित गंभीरता से नहीं निभाई गई। यदि वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मुख्यतः मंच और फोटो-सेशन पर रहा, तो विश्राम गृह जैसी संवेदनशील व्यवस्थाओं की निगरानी कमजोर पड़ना स्वाभाविक है।

क्या नियम तय करते हैं?

सरकारी सेवा आचरण नियमों में अधिकारियों को मर्यादा, निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है,किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में उनकी भूमिका प्रबंधन, समन्वय और संचालन संचालन की होती है-न कि निजी प्रचार,यदि फोटोग्राफी केवल औपचारिक दस्तावेजीकरण तक सीमित हो तो वह स्वीकार्य है,परंतु यदि यह व्यक्तिगत या सोशल मीडिया प्रदर्शन का रूप ले ले,तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

जनता बनाम फोटो-फ्रेम

मुख्यमंत्री का दौरा जनता को विकास योजनाओं की सौगात देने और जनसंवाद के उद्देश्य से था, लेकिन यदि आम नागरिकों को दूरी महसूस हुई और अधिकारी फोटो-सेशन में सक्रिय दिखे,तो यह धारणा बन सकती है कि प्राथमिकताएं उलट गईं, कई जनप्रतिनिधियों के कथित सोशल मीडिया पोस्ट और असंतोष की चर्चाएं इसी धारणा को बल देती हैं।

- देर रात विश्राम गृह में हलचल, सुबह अधिकारियों की सफाई: क्या यह प्रशासनिक चूक थी ?
- करोड़ों की सौगात के बीच 'कमरे' का विवाद: किसने मांगी माफी,कौन हुआ नाराज ?
- जब 'लिसनिंग' बनी 'पोजिंग': मुख्यमंत्री प्रवास में समन्वय की चूक पर उठे सवाल



हस्तक्षेप और 'माफ़ी' का अर्थ क्या

घटना की भनक लगते ही मामला वरिष्ठ स्तर तक पहुंचा। सूत्र बताते हैं कि देर रात जिला स्तर के उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया,संवाद के बाद स्थिति शांत हुई, यह भी चर्चा है कि अगले दिन संबंधित मंत्री से मिलकर कुछ अधिकारियों ने खेद व्यक्त किया,आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है, पर 'माफ़ी' के जरिए मामले को रफा-दफा करने की बात कही जा रही है, सवाल यह है-क्या माफ़ी प्रशासनिक चूक की स्वीकारोक्ति है, या केवल शिष्टाचार? और यदि चूक थी,तो उसकी जवाबदेही तय होगी या नहीं?

विभागीय व्यवस्थाएं और अतिरिक्त 'सुविधाएं'

सूत्रों का एक और दावा है कि भोजन-व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थीं,जिनके समन्वय में अस्पष्टता रही, देर रात यही अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी विवाद की पृष्ठभूमि बनीं, यदि एक ही परिसर में एक से अधिक मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था थी,तो वरिष्ठता और प्रोटोकॉल का संतुलन अत्यंत सावधानी से साधा जाना चाहिए था,यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा होती है।

26 वर्षों के अनुभव पर सवाल

राज्य गठन के 26 वर्षों में इस तरह की घटना का खुलकर चर्चा में आना दुर्लभ माना जा रहा है, आम तौर पर ऐसे विवाद फाइलों और बंद कमरों में सिमट जाते हैं,इस बार मामला सवालों के रूप में बाहर आया है,यह घटना केवल 'कमरे' की नहीं,बल्कि समन्वय और प्राथमिकताओं की है,जब प्रशासनिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा छवि-निर्माण में लग जाए और जमीनी प्रबंधन द्वितीयक हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं।

बड़े सवाल, जिनके जवाब जरूरी

- आवास-आवंटन की लिखित सूची और जिम्मेदार अधिकारी कौन थे?
- लाइजनिंग स्टाफ की इयुटी चार्ट और वास्तविक उपस्थिति का मिलान हुआ?
- यदि माफ़ी मांगी गई,तो किस स्तर पर और किस कारण?
- क्या भविष्य के लिए स्पष्ट SOP (Standard Operating Procedure) तैयार या संशोधित किया जाएगा?
- क्या इस प्रकरण की आंतरिक समीक्षा होगी?

कार्टवाई की दिशा क्या होगी?

- क्या आवास-आवंटन और समन्वय की निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी?
- क्या केवल निचले कर्मचारियों को दंडित कर मामला समाप्त कर दिया जाएगा?
- क्या भविष्य के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और जिम्मेदारी तय करने का लिखित आदेश जारी होगा?
- क्या आधिकारिक कार्यक्रमों में अधिकारियों की व्यक्तिगत फोटोग्राफी पर स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे?

तस्वीरों की वक्क में छिपी तीख

मुख्यमंत्री का प्रवास विकास घोषणाओं के कारण याद रखा जाएगा,पर प्रशासन के लिए यह आत्ममंथन का अवसर भी है,जब 'लिसनिंग' की जगह 'फोटो-सेशन' केंद्र में आ जाए,तो समन्वय की कड़ियां ढीली पड़ती हैं, देर रात की यह घटना भले आधिकारिक रिकॉर्ड में न हो,पर प्रशासनिक गलियारों में इसकी गूँज है, अब देखना यह है कि जिला प्रशासन पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करता है या इसे भी 'कार्यक्रम सफल रहा' की पॉकित में समेट देता है, लोकतंत्र में जवाबदेही ही व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है-और वही इस प्रकरण की अंतिम कसौटी भी होगी।

अस्वीकरण: उपरोक्त विवरण सूत्रों से प्राप्त जानकारी और उठे सवालों पर आधारित है, संबंधित पक्षों से आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

896 नग प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

सरगुजा में नशे के कारोबार पर आबकारी की बड़ी कार्टवाई,दरिमा और बतौली क्षेत्र में उड़नदस्ता टीम की दबिश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 19 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने दो मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 896 नग प्रतिबंधित स्पासो-प्रॉक्सिमीन प्लस नशीले टैबलेट जब्त किए हैं। सहलग्न जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि 18 फरवरी को उड़नदस्ता टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दरिमा थाना क्षेत्र में एक युवक बाइक से नशीले टैबलेट बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुकेश गुप्ता निवासी करजी को पकड़ लिया। उसके झोले की तलाशी में 224 नग नशीले कैप्सूल बरामद हुए।



बतौली में दो युवक पकड़े गए : इसी दिन शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि बतौली थाना क्षेत्र के सुआरपा पानी टंकी के पास दो युवक नशीले टैबलेट बिक्री के लिए



खड़े हैं। टीम ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। उनके पास से 472 नग नशीले टैबलेट जब्त किए गए। आरोपी राहुल तिग्गा और नितेश चौहान को गिरफ्तार किया गया।

तीनों आरोपी जेल भेजे गए

आबकारी विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत कार्टवाई कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। कार्टवाई में मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, कुमार राम, अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडेय, ओमप्रकाश गुप्ता एवं महिला सैनिक चंद्रावती की भूमिका रही।

झारखंड से जुड़ा है नशे का नेटवर्क

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नशीले इंजेक्शन, टैबलेट और कफ सिरप की सप्लाई का तार झारखंड के गढ़वा से जुड़ा हुआ है। वहां से लाकर सरगुजा संभाग में ऊंचे दामों पर बिक्री की जाती है। विभाग द्वारा नशा मुक्त सरगुजा अभियान के तहत कार्टवाई लगातार जारी रहेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर क्षेत्र में 259.68 लाख रु. के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केवरा,जमगला,पुहपुटारा,निम्हा, लहपटरा, खैरवार,केशवपुर, रामपुर एवं सुखरी के धान उपाजर्जन केन्द्रों में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इन धान उपाजर्जन केन्द्रों में बाउण्ड्री वाल निर्माण, कवर्ड प्लेटफार्म निर्माण तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इन सभी कार्यों पर कुल 259.68 लाख रु. की लागत से निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का रुझान है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और उपाजर्जन प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी हो। धान उपाजर्जन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से किसानों को सुरक्षित भंडारण, सुगम परिवहन और व्यवस्थित व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इससे उपाजर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान हित



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 19 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केवरा,जमगला,पुहपुटारा,निम्हा, लहपटरा, खैरवार,केशवपुर, रामपुर एवं सुखरी के धान उपाजर्जन केन्द्रों में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इन धान उपाजर्जन केन्द्रों में बाउण्ड्री वाल निर्माण, कवर्ड प्लेटफार्म निर्माण तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इन सभी कार्यों पर कुल 259.68 लाख रु. की लागत से निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का रुझान है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और उपाजर्जन प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी हो। धान उपाजर्जन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से किसानों को सुरक्षित भंडारण, सुगम परिवहन और व्यवस्थित व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इससे उपाजर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान हित

सर्वोपरि है। धान उपाजर्जन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है,ताकि गांवों में ही बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। मंत्री श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से धान खरीदी व्यवस्था और अधिक सुचारू होगी, जिससे किसानों को अनावश्यक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने,किसानों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धान उपाजर्जन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण उसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार ने धान खरीदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया को तेज किया है। सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सड़क, भंडारण और बिजली सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मंत्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि ये विकास कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और छत्तीसगढ़ को किसान कल्याण का मॉडल राज्य बनाएंगे। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा योजनाओं और जैविक खेती प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इन पहलों से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य साकार हो रहा है।

104 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दो आरोपी आय पुलिस के गिरफ्त में

-संवाददाता-

बलरामपुर, 19 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मामला थाना रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर रामनगंजण का है, दो आरोपी अवैध रूप से 104 लीटर अंग्रेजी शराब लेकर परिवहन कर रहे थे मुखबीर सूचना पर वाहन रोककर तलाशी लेने पर 104 लीटर अवैध शराब जप्त कर आरोपियों पर अपराध क्रमांक 09/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर अभिमन्यु गुप्ता पिता हरिप्रसाद गुप्ता उम्र 30 वर्ष ग्राम डोल वार्ड क्रमांक 5 थाना चिनिया जिला गढ़वा झारखंड प्रभात कुमार गुप्ता



पिता अशोक गुप्ता उम्र 23 वर्ष ग्राम डोल वार्ड क्रमांक 5 थाना चिनिया जिला गढ़वा झारखंड को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। जानकारी के अनुसार दिनांक 18/02/2026 को मुखबिर द्वारा

सूचना मिली की ग्राम डोल, थाना चिनिया, जिला गढ़वा झारखंड का अभिमन्यु गुप्ता अपने एक साथी के साथ एक सफेद रंग टाटा टैगोर कार क्रमांक jh03 अब 33.01 में गढ़वा से काफी मात्रा में अंग्रेजी

शराब बिक्री करने खुरई के रास्ते होते हुए रामचंद्रपुर की ओर जा रहा है। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश देने पर थाना प्रभारी द्वारा हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मुखबिर के बताए रास्ते पर जाकर घेराबंदी किया गया घेरा बंदी के कुछ समय पश्चात ग्राम डोल गढ़वा झारखंड की ओर से एक सफेद का कार आते दिखाई दी जिसे हाथ देखकर रुकवाया गया चालक पुलिस को देखकर अपने साथी के साथ कार छोड़कर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया

उक्त दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम अभिमन्यु गुप्ता पिता हरिप्रसाद गुप्ता उम्र 30 वर्ष ग्राम डोल वार्ड क्रमांक 5 एवं दूसरा प्रभात कुमार गुप्ता पिता अशोक गुप्ता उम्र 23 वर्ष ग्राम डोल वार्ड क्रमांक 5 थाना चिनिया जिला गढ़वा झारखंड का रहने वाला बताए। कार को गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई तलाशी के दौरान कार के अंदर 8 पेटी ब्लेंडर प्राइस चार पेटी(186 पाव) रॉयल स्टेज कुल करीब 104 लीटर अंग्रेजी शराब कुल कीमती 146820 एवं टाटा टैगोर कर कीमती 4 लाख रुपए गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है।

झुमका बना प्रयोगशाला, जनता बनी दर्शक और बजट हुआ मुख्य कलाकार



तीन बरस की 'एकतरफा बैटिंग': रिक्शे से रिटर्निंग वाल तक... विकास का महाभारत या योजनाओं का मैच ?

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/सोनहत, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। जिले में बीते तीन वर्षों के विकास कार्यों को अगर खेल की भाषा में समझें तो कुछ लोग इसे सुशासन प्रीमियर लीग बता रहे हैं, तो कुछ इसे एकतरफा बैटिंग का रिकॉर्ड मैच, आरोप है कि एक प्रभावशाली कांग्रेसी दामाद ने योजनाओं की पिच पर

ऐसी बल्लेबाजी की कि बाकी खिलाड़ी सिर्फ फील्डिंग करते रह गए, सरकारी योजनाओं की सूची लंबी है-स्वच्छ भारत मिशन, RIPA योजना, डीएमएफ मद, 15 वां वित्त, मनरेगा, शिक्षा उन्नयन, स्वास्थ्य उपकरण सप्लाई... और हर जगह वही नाम चर्चा में। समर्थक कहते हैं-काम हुआ है। विरोधी पूछते हैं-काम किसके लिए हुआ है?



मीडिया पर भी सवाल

कुछ लोग व्यंग्य में कहते हैं-करोड़ों के खेल पर दो कौड़ी की चुप्पी क्यों? पत्रकारों पर भी आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं-देखना कौन क्या देख रहा है, और कौन क्या नहीं देख पा रहा।

विकास का मॉडल या सवालों का महाभारत ?

तीन वर्षों की यह कहानी दो ध्रुवों में बंटी है एक तरफ समर्थकों का दावा है की ये ऐतिहासिक काम, दूसरी तरफ आलोचकों का आरोप है की ये ऐतिहासिक खेल, सच्चाई क्या है, यह दस्तावेज, जांच और पारदर्शिता ही तय करेगी, जनता का सवाल सीधा है क्या यह विकास का स्वर्णिम अध्याय है या योजनाओं की पिच पर खेला गया 'मैच फिक्स' ?



स्वच्छ भारत मिशन:

रिवंश चला, सवाल भी चला

सबसे पहले सफाई के नाम पर ग्राम पंचायतों में रिक्शों की खरीदी, कागजों में गांव-गांव स्वच्छता की क्रांति, फिर स्वच्छता किट की आपूर्ति-बाल्टी, झाड़ू, डस्टबिन, दस्ताने, ग्रामीणों की जुबान पर सवाल किट आई कितनी, चली कितनी, और दिखी कितनी? चरवा पारा पंचायत को एजेंसी बनाकर करोड़ों का काम-आरोप है कि मैदान में खिलाड़ी वही, स्कोर बोर्ड भी वही।

आरआईपीए योजना:

उपकरणों का 'औद्योगिक' उत्सव

ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य स्थानीय रोजगार सृजन था, लेकिन विपक्षी तंज कसते हैं, रोजगार बना या उपकरण सप्लाई का रोजगार? उपकरण खरीदी के आंकड़े करोड़ों में बताए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या स्थानीय समूहों को वास्तव में लाभ मिला या कागजों में उद्योग खड़े हो गए?

डीएमएफ मद: शिक्षा, स्वास्थ्य और

रोशनी का 'स्पेशल पैकेज'

जिला खनिज न्यास मद से सेजेस विद्यालयों में उन्नत शिक्षा संसाधन, स्पेस लैब निर्माण, जिला अस्पताल में करोड़ों की सप्लाई, मुख्यालय से लगी पंचायतों में विद्युतीकरण, स्पेस लैब की चर्चा तो खूब हुई, कुछ लोग कहते हैं, बच्चे अब चांद-तारों को समझेंगे, तो कुछ मुस्कराते हैं, पहले जमीन पर बिजली तो स्थिर कर लो !

15 वां वित्त और बिजली खंभे की परेड

ग्राम पंचायतों में बिजली खंभे और तार लगे, कुछ गांवों में खंभे ऐसे खड़े हैं जैसे लोकतंत्र की मूर्तियां-स्थिर, मौन और प्रतीक्षारत, ग्रामीण पूछते हैं-खंभा आया, तार आया...पर कंटेनर कब आएगा?

सोनहत जनपद: फाइलों की फुर्ती और

एजेंसियों की उड़ान

सबसे चर्चित आरोप सोनहत जनपद मुख्यालय से जुड़ा, लाखों की स्वीकृति, कथित फर्जी आहरण, एजेंसी गायब, खबर लगी तो नया ठेकेदार, फिर 'एडजस्टमेंट' की नई कहानी, यह सब यदि सत्य है तो यह प्रशासनिक कौशल का नया मॉडल है, काम इधर, भुगतान उधर, ठेकेदार किधर?

निजी तालाब और सार्वजनिक पैसा ?

आरोप है कि मुख्यालय स्थित निजी तालाब में लाखों की लागत से रिटर्निंग वाल घाट का निर्माण हुआ, मनरेगा जैसी योजनाओं से कथित रूप से पारिवारिक शुभचिंतकों को काम मिला, विपक्ष तंज कसता है, तालाब निजी, पैसा सार्वजनिक-इसे कहते हैं समावेशी विकास !

होटल सप्लाई और 'ओने-पौने' बिल

प्रत्येक शासकीय आयोजन में होटल से सप्लाई का आरोप, बिल ऐसे कि सुनने वाला बोले-मेन्यू में लोकतंत्र भी शामिल था क्या?

सचिव पदस्थापना का खेल

कुछ पंचायत प्रतिनिधि दावा करते हैं कि सचिवों की पदस्थापना भी प्रभाव के दायरे में रही, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है, लेकिन चर्चा गर्म है।

समर्थकों का तर्क

समर्थक कहते हैं-काम हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, विकास दिख रहा है, उनका कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट में विरोध तो होगा ही।

विरोधियों की मांग

सभी योजनाओं का स्वतंत्र ऑडिट, डीएमएफ और 15 वें वित्त मद का भौतिक सत्यापन, निविदा प्रक्रिया की जांच, जिम्मेदारी तय हो उनका कहना है, अगर सब पारदर्शी है तो जांच से डर कैसा?

उम्मीदों पर भारी निराशा

मुख्यमंत्री के कोरिया दौरे को 'घोषणाओं का झुनझुना' करार

जन सहयोग समिति के अध्यक्ष ने उठाए संभाग, मेडिकल कॉलेज और सोनहत पैकेज के मुद्दे

-संवाददाता-

कोरिया, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हालिया कोरिया दौरा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां सत्तापक्ष इसे विकास कार्यों की नई शुरुआत बता रहा है, वहीं विपक्ष राजवाड़े, अध्यक्ष कोरिया जन सहयोग समिति, ने इसे घोषणाओं का झुनझुना बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है, मुख्यमंत्री के प्रस्थान के बाद मीडिया से चर्चा में राजवाड़े ने कहा कि कोरिया की जनता जिस ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी, वह केवल आश्वासनों तक सीमित रह गया, उनके अनुसार, जिले को संभाग का दर्जा दिए जाने की व्यापक उम्मीद थी, लेकिन इस पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई।

संभाग का दर्जा: सबसे बड़ा सवाल

राजवाड़े ने कहा कि कोरिया को संभाग का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। उनका आरोप है कि दौरे से पहले माहौल ऐसा बनाया गया था मानो इस पर सकारात्मक निर्णय होगा, किंतु अंततः इस विषय पर मौन साध लिया गया, उन्होंने कहा कि संभाग बनने से प्रशासनिक शक्ति बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर फैसले तेजी से होंगे और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर नाराज़गी

विपक्षी स्वर में राजवाड़े ने मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं की घोषणा न होने को जिले के भविष्य के साथ अन्याय बताया, उनका कहना है कि यदि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती, तो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता बल्कि स्थानीय युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर भी मिलते, उन्होंने यह भी कहा कि जिला अस्पताल की वर्तमान स्थिति और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की मांग अत्यंत आवश्यक है।

सोनहत और वनांचल क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप

राजवाड़े ने विशेष रूप से सोनहत और अन्य दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन इलाकों के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज या ठोस कार्ययोजना सामने नहीं आई, उन्होंने कहा कि भौगोलिक विषमता और आदिवासी बहुल आबादी को देखते हुए अलग से विकास मॉडल की आवश्यकता है।

अटके विकास कार्यों पर सवाल



पूर्ववर्ती सरकार के समय स्वीकृत सड़क और विद्युतीकरण परियोजनाओं का जिक्र करते हुए राजवाड़े ने आरोप लगाया कि बजट के अभाव में कई कार्य ठप पड़े हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री दौरे के दौरान इन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए स्पष्ट वित्तीय खाका प्रस्तुत नहीं किया गया।

बाईपास नहीं, दूरदृष्टि चाहिए

राजवाड़े ने कहा कि केवल सड़कों के पैचवर्क, चौड़ीकरण या बाईपास से जिले का समग्र विकास संभव नहीं है, उनके शब्दों में, कोरिया को प्रशासनिक मजबूती और बड़े संस्थानों की जरूरत है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि बुनियादी जरूरतें आज भी फाइलों में कैद हैं।

सत्तापक्ष का रुख

हालांकि सत्तापक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और आने वाले समय में योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया जाएगा, उनका दावा है कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर काम होगा।

राजनीतिक तापमान बढ़ा

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कोरिया में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे जनभावनाओं की अनदेखी बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे विकास यात्रा का आरंभ मान रहा है, अब नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले महीनों में कोई ठोस प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है या यह बहस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी।

स्टेट हार्डवे पर खुदाई, बिना अनुमति पाइप लाइन ?

जल जीवन मिशन के कार्य में खड़गवां से उठे गंभीर सवाल



-संवाददाता-

एमसीबी/खड़गवां, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना के तहत चल रहे कार्य अब खड़गवां मुख्यालय में विवादों के घेरे में आ गए हैं, आरोप है कि स्टेट हार्डवे से महज कुछ फीट की दूरी पर लगभग दो से तीन किलोमीटर तक सड़क की खुदाई कर पाइप लाइन बिछाई जा रही है-वह भी बिना लोक निर्माण विभाग की अनुमति के, मामले ने न केवल निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े किए हैं, बल्कि विभागीय समन्वय और जवाबदेही पर

भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सड़क किसकी, अनुमति किसकी ?

ग्रामीणों के अनुसार जब उन्होंने मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन और कार्य देखेख कर रहे मुंशी से पूछताछ की, तो बताया गया कि अनुमति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से ली गई है, लेकिन सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि: क्या लोक निर्माण विभाग से विधिवत निर्माण विभाग की अनुमति के, मामले ने न केवल निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े किए हैं, बल्कि विभागीय समन्वय और जवाबदेही पर

संभावित खतरे...

भविष्य में स्टेट हार्डवे का चौड़ीकरण होने पर पाइप लाइन टूटने की आशंका

जल आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को दोबारा संकट का सामना

सार्वजनिक धन का संभावित दुरुपयोग

विभागीय समन्वय की कमी से प्रशासन की साख पर असर

संजय भरिलया ने स्पष्ट कहा कि उनके विभाग द्वारा सड़क खुदाई की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

गुणवत्ता पर गंभीर आरोप

ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि-पाइप लाइन निर्धारित गहराई से कम पर डाली जा रही है, कई स्थानों पर पाइप ऊपर से दिखाई दे रही है, सड़क किनारे बेहद कम दूरी पर पाइप बिछाई गई है, जिससे भविष्य में चौड़ीकरण होने पर पूरी लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है, यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल तकनीकी मानकों की अनदेखी है बल्कि करोड़ों रुपये की योजना के भविष्य को भी खतरे में डाल सकता है।

निरीक्षण और निगरानी पर सवाल

आरोप यह भी है कि मनेंद्रगढ़ उपखंड अंतर्गत पीएचई के अधिकारी नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे, ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, यदि स्थल निरीक्षण नियमित होता, तो-उथली गहराई में पाइप डालने, बिना अनुमति सड़क खुदने, और गुणवत्ता में कमी, जैसी बातें सामने ही नहीं आतीं।

करोड़ों का बजट, लेकिन क्या मानक पूरे ?

2019 से प्रारंभ हुई इस योजना का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भारी बजट उपलब्ध कराया गया है, लेकिन यदि कार्य मानकों के विपरीत हो रहे हैं, तो यह योजना की मूल भावना के साथ अन्याय होगा, पाइप लाइन यदि भविष्य में क्षतिग्रस्त होती है, तो पुनः खुदाई, मरम्मत और अतिरिक्त खर्च का भार अंततः जनता पर ही पड़ेगा।

जिम्मेदारी तय होनी चाहिए...

ऐसे मामलों में निम्न बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है-सड़क खुदाई की अनुमति और दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, पाइप लाइन की थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच कराई जाए, तकनीकी मानकों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, भविष्य में संयुक्त निरीक्षण प्रणाली लागू की जाए।

बड़ा प्रश्न

क्या हर घर जल का सपना जल्दबाज़ी और अनियमितता की भेंट चढ़ जाएगा? या जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगा? यह मामला केवल एक सड़क या पाइप लाइन का नहीं है-यह योजना की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे का प्रश्न है।

कोरिया जिला न्यायालय में भी आयोजित हुआ शोक शांति कार्यक्रम

अधिवक्ता अजय सिंह ने दी जानकारी, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किया गया सामूहिक मौन

कोरिया, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती कुसुम सिन्हा के निधन पर कोरिया जिला न्यायालय परिसर में भी शोक-शांति कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस संबंध में अधिवक्ता अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और न्यायालय कर्मचारी उपस्थित रहे।

दो मिनट का मौन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि-

कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थितजनों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय श्रीमती कुसुम सिन्हा के सादरीपूर्ण जीवन, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों का स्मरण किया, अधिवक्ता अजय सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम न्यायपालिका परिवार की संवेदनशीलता और एकजुटता का प्रतीक है, उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर में वातावरण पूर्णतः गंभीर और भावनात्मक रहा।

न्यायिक परिवार की सहभागिता-श्रद्धांजलि सभा में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, वरिष्ठ

अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

संवेदना और सम्मान का संदेश-कोरिया जिला न्यायालय में आयोजित यह कार्यक्रम न्यायिक परंपरा और मानवीय संवेदना का उदाहरण बना, न्यायालय परिवार ने एक स्वर में कहा कि दिवंगत आत्मा की स्मृतियां सदैव प्रेरणा देती रहेंगी, श्रद्धा, सम्मान और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ यह शोक-शांति कार्यक्रम न्यायपालिका के मानवीय पक्ष को भी उजागर करता है।



रेखा को दी टक्कर,लंबाई ने फ्लॉप कराया करियर

खान्स पर आरोप लगाने वाली 90 दशक की बोल्ड हीरोइन आज है गुमनाम

80 और 90 के दशक में कई हीरोइन्स स्टारडम के शिखर पर थीं और इसी बीच कुछ नई एक्ट्रेसेंस आईं, जिन्होंने सिनेमा की परिभाषा बदली। जहां सूट और साड़ी में रहने वाली हीरोइनें थें तो वहीं इसी बीच 5 फीट 8 इंच की एक लंबी हसीना ने सिनेमा का समीकरण बदल दिया।

70 और 80 के दशक में नई अभिनेत्रियों का आने का दौर एकदम से शुरू हुआ था। उस दौर में पहले से ही कई हीरोइन्स स्टारडम के शिखर पर थीं और इसी बीच कुछ नई एक्ट्रेसेंस आईं, जिन्होंने सिनेमा की परिभाषा बदली। जहां सूट और साड़ी में रहने वाली हीरोइनें थें तो वहीं इसी बीच 5 फीट 8 इंच की एक लंबी हसीना ने सिनेमा का समीकरण बदल दिया।जीनत अमान और परवीन बाबी के बाद ये वो अभिनेत्री थी,जिसे तगड़ा कॉम्पटीशन माना जा रहा था। हॉट विलेन बनकर उसने खुब तारीफें भी बटोरीं, लेकिन कैसे ये हीरोइन गुमनामी के अंधेरे में खो गई? कैसे रतोंरात स्टार बनी इस हसीना को सबने भुला दिया?

आते ही स्टार बनी थीं सोनू वालिया

जिस एक्ट्रेस की आज हम बात कर रहे हैं, वो हैं सोनू वालिया । वही सोनू वालिया,जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर आकर खूब चर्चा बटोरी तो वहीं उनके करियर में एक वक्त वो आया को बिल्कुल गुमनाम हो गई और उन्होंने इसके आरोप इंडस्ट्री के तीनों खान्स पर लगाए। सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 को नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था।

सोनू ने साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की, साथ ही वो जर्नलिज्म की भी स्टूडेंट रहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनू मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते इसी फील्ड में आ गईं। इसी बीच उन्होंने साल 1985 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। खूबसूरत और लंबी होने के चलते सोनू वालिया के पास ये खिताब आसानी से आ गया। हालांकि इसके पीछे उनकी मेहनत भी खूब रही। ग्लैमर की दुनिया में आते ही सोनू छ ग गईं और फिर आखिरकार वक्त उनके डेब्यू का। साल 1986 में फिल्म शर्त से उन्होंने डेब्यू किया लेकिन इसमें वो एक मॉडल के तौर पर दिखीं, पर असली उनकी किस्मत बदली रेखा के साथ आई एक फिल्म से।

खून भरी मांग में रेखा को दी टक्कर

साल 1988 में सोनू वालिया फिल्म खून भरी मांग में नजर आईं। असल मायनो में यही सोनू वालिया की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने नंदिनी का निगेटिव रोल निभाया। फिल्म में वो रेखा और कबीर बेदी जैसे सुपरस्टार्स के साथ दिखीं। सोनू का किरदार फिल्म में काफी बोल्ड रहा। उन्होंने बिकिनी और स्विमसूट पहनकर सनसनी मचा दी। फिल्म में उन्होंने 20 साल बड़े कबीर बेदी से रोमांस किया था, जो खूब चर्चा का विषय रहा। कई लोगों को तो ये लगा कि फिल्म में सोनू के चलते रेखा पर लोगों की नजरें कम गइं। इस फिल्म के लिए सोनू वालिया को फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला।

लंबाई ही बन बैठी दुश्मन

उस दौर में ज्यादा लंबी हीरोइनें नहीं हुआ करती थीं, लेकिन सोनू वालिया की लंबाई अच्छी खासी थी। ऐसे में सोनू वालिया के साथ काम करने से लोग कतराते थे। दरअसल उस दौर में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, समेत कई स्टार्स थे, जो सोनू के साथ काम करने से कतराते थे। दरअसल अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेद, सनी देओल, विनोद खन्ना, और कबीर बेदी जैसे लंबे स्टार्स के साथ सोनू पहले ही काम कर चुकी थीं। हालांकि बाद में जब खान्स का दौर आया तो सोनू को परेशानी हुई। खुद सोनू वालिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि,खान्स के आने के बाद फिल्मों में काम मिलना लगभग कम हो गया।

बी-ग्रेड फिल्मों के बाद छोटे पर्दे पर भी किया काम

सोनू वालिया के करियर में कोई ऐसी सिंगल सोलो हीरोइन वाली फिल्म नहीं रही, जिसे ब्लॉकबस्टर कहा जा सके। हालांकि उन्होंने शाहरुख के साथ फिल्म दिल आशना में काम जरूर किया था। इसके अलावा वो महदेव,तूफान,अपना देश पपाए लोग,तहलका,हातिम ताई, तेजा, खेल और प्रतिकार समेत कई फिल्मों में दिखीं। हालांकि जब ये फिल्में नहीं मिलीं, तो उन्होंने बी-ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। बी-ग्रेड फिल्मों के बाद उन्होंने छोटे पर्दे का भी रुख किया।

पति का भी छूटा साथ

सोनू वालिया ने फिल्मों में खूब हाथ-पैर मारे,लेकिन वो लीड हीरोइन वाली सक्सेस उन्हें कभी नहीं मिली। फिल्में नहीं चली तो फिर उन्होंने अपना घर बसा लिया। साल 1995 में उन्होंने विजनेस्मैन सूर्य प्रकाश से शादी की। शादी के बाद उन्होंने विदेश रहने का मन बनाया और वो पति के साथ वहाँ शिफ्ट हो गईं। लेकिन साल 2009 में उनके पति का निधन हो गया और इसके बाद वह फिर से अकेली पड़ गईं। सोनू वालिया ने सिनेमा के सुनहरे दौर में काम किया। हालांकि इतनी खूबसूरत और फिट होने के बाद भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाईं और यही वजह है कि, शायद उनका ज्यादा खूबसूरत और लंबा होना उनके करियर पर भी भारी पड़ा।

शुरू हुई रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां,लाइटों से सजा एक्टर का घर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें इन दिनों खूब चर्चा में हैं। सूत्रों के अनुसार,उनकी शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक हिल रिसॉर्ट में होगी, जिसके बाद 4 मार्च को रिसेप्शन दिया जाएगा। यह एक बेहद निजी समारोह होगा।

श्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें इन दिनों बॉलीवुड में खूब चर्चा में हैं। खबरों के मुताबिक, उनकी शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हाल ही में विजय देवरकोंडा के घर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसे लाइटों से सजाया गया है।इसके बाद शादी के कार्ड की फोटो भी खूब वायरल हो रही है। अब दोनों के शादी के कार्ड से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। वेडिंग इन्विटेशन के लिए खासतौर से एक बॉक्स तैयार किया गया है।

कहां होगी विजय-रश्मिका की शादी?

सूत्रों के अनुसार, शादी उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक हिल रिसॉर्ट में होगी। जानकारी के

सोशल मीडिया पर हो रही एल्विश यादव के शो इंगेज्ड सीजन 2 की छीछलेदर,फैंस बोले...कैसा अश्लील शो है...



ने टवीट किया, इंगेज्ड सीजन 2 में ये किस तरह का टास्क है? वायरल हो रहा लैप डांस का वीडियो

इसके बाद एक दूसरा टास्क था लैप डांस चैलेंज।

एल्विश यादव और जिया शंकर द्वारा होस्ट किया गया शो इंगेज्ड सीजन 2 अपने बोल्ड और बेहूदा टास्क के कारण विवादों में है। 14 फरवरी, 2026 को शुरू हुए इस शो में लैप डांस, मिट्टी फेंकना और बर्फ के चैलेंज जैसे टास्क शामिल हैं। इन अजीबोगरीब टास्क को लेकर दर्शक सोशल मीडिया पर शो की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसे भद्दा व अश्लील बता रहे हैं।

एल्विश यादव और जिया शंकर इंगेज्ड सीजन 2 के होस्ट हैं। शो वेलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी,2026 को शुरू हुआ। पहले सात एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और फिलहाल जियो हॉटस्टार पर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। नए सीजन में कई सारे बोल्ड टास्क फैंस को दिए गए जिनमें लैप डांस चैलेंज, आइस क्यूब चैलेंज और सड़ टास्क शामिल हैं।

शो में दिए जा रहे बेहूदा टास्क

शुरुआती टास्क में से एक में फीमेल कंटेस्टेंट को घर में मौजूद उस कंटेस्टेंट पर मिट्टी फेंकने के लिए कहा जो फेक है। इसके बाद पुरुष कंटेस्टेंट्स से कहा गया कि वो उनके शरीर से मिट्टी साफ करें। फैंस इस तरह के अजीब टास्क देखकर ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर



अनुसार यह शादी अरावली पर्वतमाला में बसे उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित आईटीसी

होटल्स के द मोमेंटोस में होगी। इस हिल रिसॉर्ट को इसलिए चुना गया है क्योंकि ट्रल्हा-दुल्हन



कटरीना कैफ के बेटे के लिए आलिया भट्ट ने भिजवाया इतना प्यारा तोहफा ,एक्ट्रेस ने दिखाई फोटो

कटरीना कैफ के बेबी ब्वॉय के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक प्यारा सा तोहफा भिजवाया, जिसकी तस्वीर शेयर करने से एक्ट्रेस खुद को रोक नहीं पाईं। पिछले साल नवंबर के महीने में कटरीना कैफ और विक्की कौशल पहली बार माता-पिता बने। जब से एक्ट्रेस मां बनी हैं,तभी से वह लाइमलाइट से दूर हैं और अपने बेटे के साथ काल्पिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं।

कटरीना कैफ का बेबी ब्वॉय हाल ही में तीन महीने का हो गया है। अब एक्ट्रेस के बेटे के लिए आलिया भट्ट की तरफ से प्यारा सा तोहफा भेजा गया है।

आलिया ने भेजा कटरीना के बेबी के लिए तोहफा

कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने आलिया भट्ट की तरफ से भेजे गए गिफ्ट्स की झलकियां शेयर की हैं। आलिया भट्ट के क्लोटिंग ब्रांड इडामम्मा ने कटरीना के बेबी ब्वॉय के लिए क्यूट सा खिलौना और कपड़ा भेजा। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, इन प्यारे कडलीज के लिए थैंक यू इडामम्मा ।

वया है कटरीना कैफ के बेटे का नाम?

कटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 नवंबर 2025 को माता-पिता बने थे। कपल ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है। कपल ने अपने बेटे के नाम की अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन अभी तक बेबी का चेहरा रिवील नहीं किया है। कपल के बेटे का देखने के लिए लोग बताव हैं।

कटरीना कैफ और आलिया भट्ट का वर्क फ्रंट

कटरीना कैफ को आखिरी बार मेरी क्रिसमस मूवी में देखा गया था। इसके बाद से ही एक्ट्रेस फिल्मी वर्ल्ड से गायब हैं। वहीं,आलिया भट्ट लव एंड वॉर में विक्की कौशल और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास अल्फा मूवी भी है।

खेल समाचार

वेस्टइंडीज की टी-20 वर्ल्डकप में लगातार चौथी जीत

इटली को 42 रन से हराया
शार्ड होप का अर्धशतक,शमार जोसेफ को 4 विकेट

कोलकाता, 19 फरवरी 2026। वेस्टइंडीज ने टी-20 वर्ल्डकप के 37वें मुकाबले में इटली को 42 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की इस वर्ल्डकप में यह लगातार चौथी जीत है। गुरुवार को दिन के पहले मैच में इटली ने कोलकाता के इंडन गार्डन्स में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए हैं। जवाब में इटली 18 ओवर में 123 रन पर ऑलआउट हो गई।गुप्पू-सी का यह आखिरी मुकाबला था।166 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इटली के लिए बेन मैनेंटी ने 26, जेजे स्मट्स ने 24, एंथोनी मोस्का ने 19 और ग्रांट स्टीवर्ट ने 12 रन बनाए। बाकी 7 बैटर्स दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। वेस्टइंडीज के लिए शमार जोसेफ ने 4, मैथ्यू फोर्ड ने 3 और गुडकेश मोती ने 2 विकेट लिए। अकील हुसैन को भी 1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज के लिए शार्ड होप ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 46 बॉल पर 75 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा, रोस्टन चेज 24 और शेरफन रदरफोर्ड



ने नाबाद 24 रन बनाए। इटली के लिए क्रिशन कलुगामागे और बेन मैनेंटी ने 2-2 विकेट लिए। अली हसन और थॉमस झुका को 1-1 विकेट मिला।

फोर्ड ने मिड को आउट किया मैथ्यू फोर्ड ने 17वें ओवर में जियान मीड को पवेलियन भेज दिया। यह इटली का 8वां विकेट रहा। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ बॉल पर मीड ने ड्राइव खेलने के लिए हाथ फैलाए, लेकिन शॉर्ट सीधा कवर-पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चला गया। वहां शमार जोसेफ ने आसान कैच लपकते ही हल्का सा जश्न भी

मनाया। मीड 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए।

गुडकेश मोती ने बेन को बोल्ड किया गुडकेश मोती ने 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर बेन मैनेंटी को बोल्ड कर दिया। बेन 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था।
शमार ने स्टीवर्ट को आउट किया शमार जोसेफ ने 15वें ओवर में फुल लेंथ गेंद सीधे स्टंप्स पर डाली। ग्रांट स्टीवर्ट ने क्रीज से हटकर फंट फुट खाली किया और बड़ा शॉट खेलने

की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही दिशा नहीं दे सके। लॉग-ऑफ पर फ्रीलैंडिंग कर रहे जोसन होल्डर ने आसान कैच लपक लिया। वे 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक छक्का शामिल था।

फोर्ड को दूसरा विकेट, नकवी आउट मैथ्यू फोर्ड ने छठे ओवर की आखिरी बॉल पर सैयद नकवी को आउट कर दिया। नकवी शुरुआत से ही संघर्ष करते नजर आ रहे थे और खुलकर शॉट नहीं लगा पा रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद पर उन्होंने बड़ा ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में ऊंची उठ गई और मिड-ऑफ के ऊपर चली गई। वहां शमरा जोसेफ ने पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच ले लिया। नकवी 10 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए।

अकील ने एंथनी मोस्का को आउट किया अकील हुसैन ने इटली को दूसरा झटका दिया। उन्होंने गेंद को दाएं हाथ के बल्लेबाज एंथनी मोस्का को आउट कर दिया। मोस्का ने स्वीप शॉट खेलने के लिए काफी मूव किया, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को उठाने में नाकाम रहे। वहां शमार जोसेफ ने आसान कैच लपक

लिया। आउट होने के बाद मोस्का खुद से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने 12 गेंदों पर 19 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे।

फोर्ड ने जस्टिन मोस्का को बोल्ड किया

दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मैथ्यू फोर्ड ने वेस्टइंडीज को शुरुआती सफलता दिला दी। उन्होंने जस्टिन मोस्का को बोल्ड कर दिया। मोस्का बैकफुट पर ड्राइव खेलने गए, लेकिन जगह की कमी के कारण बल्ले और पैड के बीच बड़ा गैप रह गया। गेंद उसी गैप से निकलकर ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकरा गई। मोस्का 5 गेंदों में 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए।

दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन
इटली:- हैरी मैनेंटी (कप्तान), जस्टिन मोस्का, एंथोनी मोस्का, सैयद नकवी, जेजे स्मट्स, बेन मैनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीड (विकेट कीपर), क्रिशन कलु गमागे, थॉमस झुका,अली हसन।
वेस्टइंडीज:- बैंडन क्रिग, शार्ड होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमन पवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकिल हुसैन, गुडकेश मोती, शमार जोसेफ।

हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलकर इतिहास रचा



नई दिल्ली, 19 फरवरी 2026।

ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट का सालों पुराना सपना पूरा करने वाली हरमनप्रीत कौर ने नए साल में इतिहास रच दिया। उन्होंने टीम इंडिया को पहली आईसीसी ट्रांफी दिलाने वाली कप्तान के तौर पर रिकॉर्ड बनाया था। इस बार उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दिग्गजों के लिए नामुमकिन था। हरमनप्रीत इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला बन गई हैं। हरमनप्रीत ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर दूसरे ३20 में खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। अपने धमाकेदार खेल से भारतीय टीम की

अहम बल्लेबाज के तौर पर उभरी हरमनप्रीत कौर अपने नाम कई रिकॉर्ड लिख रही हैं। लंबे इंतज़ार को खत्म करते हुए.. टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली हरमनप्रीत ने.. सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सीनियर बल्लेबाज सुजी बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए...भारतीय कप्तान ने अपना 356वां मैच खेला। बचपन से ही क्रिकेट पर ध्यान देने वाली इस पंजाबी लहर ने 2009 में डेब्यू किया था। वह जल्द ही तीनों फॉर्मेट में छा गईं। हरमनप्रीत, जिन्होंने कभी भारत के लिए मिताली राज को पीछे छोड़ा था, अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर बेट्स से आगे निकल गई हैं। उन्होंने अब तक छह टेस्ट, 161 ओडीआई और 189 टी20 आई खेले हैं। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटरों की लिस्ट में एलिसा पेरी (ऑस्ट्रेलिया) 349, मिताली राज (भारत) 333, चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) 309 और सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) 305 मैचों के साथ अगले नंबर पर हैं।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया

कोलंबो,19 फरवरी 2026। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और बड़ा उलटफेर किया है। गुरुवार को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 38वें मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका से मिले 179 रनों के लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर के साथ ही जिम्बाब्वे ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में यह जिम्बाब्वे का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है। इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में यह श्रीलंका के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा रन चेज भी है। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कुल 7 छक्के जमाए, जो टी20



दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सीन विलियम्स की बराबरी कर ली है। बेनेट और विलियम्स ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 12 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है।

दवा थी या सिर्फ सफेद गोली ? लैब ने कहा फेल, सिस्टम अब भी पास ?

लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा...तीनों सैपल ‘Not of Standard Quality’, दवा में एक्टिव साल्ट शून्य

जब गोली में दवा नहीं,तो जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य खतरे में,कार्रवाई कागजों में ! जनता बीमार,तंत्र बेखबर?

छत्तीसगढ़ में नकली एंटीबायोटिक का जाल: लैब रिपोर्ट में ‘0.0 mg’ एक्टिव साल्ट,निरीक्षण से सीज तक सब दर्ज—फिर कार्रवाई कहीं अटक?
दवा के नाम पर धोखा! तीन सैपल फेल,एक्टिव साल्ट निकला शून्य
सफेद गोली या मौत का सौदा? एंटीबायोटिक में दवा ही नहीं मिली
Form-13 की रिपोर्ट से सनसनी : मरीजों को मिली बिना दवा की दवा

जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़: लैब में फेल,फिर भी कार्रवाई अछूरी?
दवा में दवा नहीं: सरकारी लैब रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
स्टॉक जटिल, मोबाइल सीज,रिपोर्ट फेल... फिर FIR क्यों नहीं?

न्यूज डेस्क
रायपुर, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ में नकली या संदिग्ध गुणवत्ता वाली एंटीबायोटिक दवाइयों के कथित नेटवर्क पर अब दस्तावेजी परतें खुलने लगी हैं, निरीक्षण आदेश, जव्ती पंचनामा, मोबाइल सीज, और अंततः शासकीय प्रयोगशाला की Form-13 (Section 25(1), Drugs × Cosmetics Act, 1940) के तहत जारी रिपोर्ट—सभी कड़ियाँ एक ही दिशा में इशारा करती हैं। तीन अलग-अलग सैपलों की लैब रिपोर्टों में दवा किए गए सक्रिय साल्ट की मात्रा 0.0 mg पाई गई और निष्कर्ष दर्ज हुआ— Not of Standard Quality ‘। यह केवल ‘कम गुणवत्ता’ का मामला नहीं; यदि अंतिम कार्बोनिज परीक्षण में तथ्य पुष्ट होते हैं तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ गंभीर छल का मामला बन सकता है। नीचे पूरे घटनाक्रम, दस्तावेज और कानूनी पहलुओं को समेटती विस्तृत रिपोर्ट— बता दे की दिसंबर 2025 की कार्रवाई, मोबाइल सीज, और 16/12/2025 की Form-13 लैब रिपोर्ट—तीनों मिलकर एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं: दवा किए गए सक्रिय साल्ट 0.0 mg, यह तथ्य यदि विधिक कसौटी पर कायम रहता है,तो मामला साधारण गुणवत्ता दोष से कहीं आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ बड़े छल का रूप ले सकता है,अब निगाहें अभियोजन की प्रगति, विभागीय पारदर्शिता और सप्लाई चेन की संपूर्ण जांच पर हैं। छत्तीसगढ़ में दवा की विश्वसनीयता तभी लौटेंगी जब कानूजी कार्रवाई अदालत तक पहुँचे और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो।

घटनाक्रम की शुरुआत: आदेश,निरीक्षण और जव्ती

हस्ताक्षरकर्ता औषधि निरीक्षक हेमंती नारायण सिंह का नाम दर्ज है, दस्तावेज बताते हैं कि बिल/जीआर के आधार पर स्टॉक का मिलान किया गया, नमूने लिए गए और शेष सामग्री को विधिवत जब्त कर अभिरक्षा में लिया गया।

जब्त दवाइयों (दस्तावेज अनुसार)

- CUMOX CV-625 (Amo×4cillin + Clavulanate + Lactic Acid Bacillus)
- G-CEF AZ (Cefi&ime + Azithromycin + Lactic Acid Bacillus)
- ARRCF-AZ (Cefi&ime + Azithromycin + Lactic Acid Bacillus)

दस्तावेज में बैच नंबर, निर्माण/समाप्ति तिथि और लेबल पर दर्शाए गए निर्माताओं का विवरण भी दर्ज है।

डिजिटल साक्ष्य: मोबाइल सीज

निरीक्षण के दौरान फर्म संचालक के पुत्र वंश केसरवानी के मोबाइल (Gala×4 AS4 5G; IMEI विवरण दर्ज) की गैलरी में जव्त दवा का फोटो मिलने का उल्लेख है, प्रपत्र-16 के तहत मोबाइल सीज कर अभिरक्षा में लेने की कार्रवाई भी दर्ज है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्लाई चेन, बिलिंग और संचार की डिजिटल कड़ियाँ अक्सर ऐसे मामलों में निर्णायक साबित होती हैं।

रास्ता खट्ठों में

टैबलेट में एंटीबायोटिक का सक्रिय घटक शून्य पाया गया,यह निष्कर्ष अगर विधिक प्रक्रिया में कायम रहता है, तो मरीजों को दवा के नाम पर केवल भराव सामग्री मिलने का संकेत देता है।

‘Not of Standard Quality’ बनाम ‘Spurious’ —कानूनी फर्क— Drugs & Cosmetics Act, 1940 के तहत ‘Not of Standard Quality (NSQ)’ का अर्थ है कि दवा निर्धारित फार्माकोपिया या देश में पहले की तरह मनरेगा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि,मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका का बड़ा सहारा है।

पहचान,या जानबूझकर धोखे की मंशा शामिल हो सकती है,यह अंतिम निर्धारण जांच,निर्माता से स्पष्टीकरण,और न्यायालयीन परीक्षण के बाद ही होता है। परंतु 0.0 mg सक्रिय साल्ट का तथ्य मामले को अत्यंत गंभीर बनाता है।

जनस्वास्थ्य पर प्रभाव: एंटीबायोटिक रैजिस्ट्रेशन का खतरे-

ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक श्रेणी की हैं—Cefixime, Azithromycin, Amo&yacillin जैसी दवाएँ बैक्टीरियल संक्रमण में व्यापक रूप से दी जाती हैं, यदि मरीज को सक्रिय घटक रहित गोली दी जाए: संक्रमण नियंत्रण में विफलता, बीमारी का बिगड़ना, अस्पताल में भर्ती की नौबत, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का दीर्घकालिक खतरा, विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने नकली/NSQ एंटीबायोटिक को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती माना है।

निर्माताओं की भूमिका और बॉड प्रोटेक्शन

रिपोर्ट में लेबल पर दर्शाए गए निर्माताओं के नाम/लाइसेंस नंबर अंकित हैं,ऐसी स्थिति में दो संभावनाएँ होती हैं—ब्रांड/लेबल की जालसाजी व सप्लाई चेन में किसी स्तर पर मिलावट/री-पैकिंग निर्माता कंपनियों का आधिकारिक पक्ष,बैच-रिकॉल रिकॉर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेल की फॉरेंसिक ऑडिट—इन सबकी जांच जरूरी है। यदि लेबल असली है तो उत्पादन स्तर पर गंभीर प्रश्न,यदि लेबल फर्जी है तो ब्रांड-इम्पर्सनेशन का मामला।

डिजिटल फॉरेंसिक: मोबाइल डेटा की अहमियत

सीज किए गए मोबाइल से— फोटो मेटाडेटा (तारीख/लोकेशन),चैट/कॉल रिकॉर्ड, बिलिंग/पेमेंट स्क्रीनशॉट,सप्लाई समन्वय जांच एजेंसियाँ महत्वपूर्ण कड़ियाँ जोड़ सकती हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस मामले में निर्णायक हो सकती है।

जवाबदेही और विश्वास

दवा पर भरोसा स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है। निरीक्षण से लेकर लैब रिपोर्ट तक की

सप्लाई चेन: ट्रांसपोर्ट से स्टॉकिंग तक...

दस्तावेज में जीआर नंबर और बिल का उल्लेख है, बिल असली दवा के नाम का पर सामग्री संदिग्ध—ऐसी स्थिति में जांच को निम्न कड़ियों तक पहुँचना होगा: ट्रांसपोर्ट की भूमिका, सप्लायर/स्टॉकिंग,लेबल पर दर्शाए गए निर्माता,थोक विक्रेता/रिटेलर,लाइसेंस अथॉरिटी की निगरानी यदि तीन अलग-अलग ब्रांड/बैच में समान प्रकृति की कमी (0.0 mg) पाई गई,तो यह अलग-थलग घटना नहीं बल्कि संगठित गड़बड़ी का संकेत हो सकता है—हालाँकि अंतिम निष्कर्ष जांच पर निर्भर करेगा।

विभागीय जवाबदेही प्रक्रिया आगे बढ़ी या रुकी?

दस्तावेज बताते हैं कि नमूने विधिवत लिए गए,न्यायालय से अभिरक्षा अनुमति हेतु आवेदन किया गया,लैब रिपोर्ट जारी हुई, बड़ा प्रश्न यह है कि अभियोजन की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या संबंधित पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? क्या लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण की कार्रवाई हुई? क्या DCGI/राज्य नियंत्रक को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया? क्या निर्माता कंपनियों से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ? पारदर्शिता के लिए विभाग को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रक्रिया दस्तावेजों में दर्ज है। अब जनता यह जानना चाहती है कि—दोषियों पर कब और कैसे कार्रवाई होगी? क्या प्रभावित बैच का राज्यव्यापी रिकॉल हुआ? क्या मरीजों/डॉक्टरों को अलर्ट जारी किया गया? पारदर्शी कार्रवाई ही विश्वास बहाल कर सकती है।

नकली एंटीबायोटिक का जाल छत्तीसगढ़ में

हकीकत या सिर्फ सफेद गोली?



✓ नकली दवा का स्टोक पकड़ा गया

✓ लैब रिपोर्ट: एक्टिव साल्ट 0.0 mg

सबक? जनता का स्वास्थ्य खतरे में, फिर भी FIR का इन्तजार

लैब रिपोर्ट ‘0.0 mg’ का खुलासा-

शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी Form-13 रिपोर्ट (दिनांक 16/12/2025) में तीनों सैपलों के बारे में निम्न निष्कर्ष दर्ज हैं...

1) ARRCF-AZ (Report No. 390) ■ दवा: Cefixime 200 mg + Azithromycin 250 mg ■ Found: 0.0 mg (दोनों साल्ट) ■ Identification: Fail ■ Assay: Fail ■ निष्कर्ष : Not of Standard Quality	2) G-CEF AZ (Report No. 389) ■ दवा: Cefixime 200 mg + Azithromycin 250 mg ■ Found: 0.0 mg (दोनों साल्ट) ■ Identification/Assay: Fail ■ निष्कर्ष : Not of Standard Quality
3) CUMOX CV-625 (Report No. 391) ■ दवा: Amoxycillin 500 mg + Clavulanate 125 mg ■ Found: 0.0 mg (Amoxycillin) ■ Identification/Assay: Fail ■ अतिरिक्त टिप्पणी: लेबलिंग/मोनोग्राफ संबंधी आपत्ति ■ निष्कर्ष : Not of Standard Quality	

डिस्क्लेमर

यह समाचार उपलब्ध दस्तावेजों,निरीक्षण रिपोर्ट,जव्ती पंचनामा तथा शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की Form-13 रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है,इसमें उल्लिखित तथ्य संबंधित विभागीय अभिलेखों एवं लेब विश्लेषण में दर्ज निष्कर्षों पर आधारित हैं,इस समाचार में जिन व्यक्तियों,संस्थाओं या कंपनियों के नामों का उल्लेख है,उन्हे विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक जिम्मेदारी या दोष सिद्धि का अंतिम निर्णय केवल सक्षम जांच एजेंसी एवं न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा.समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना नहीं,बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना है,यदि संबंधित पक्ष इस विषय में अपना आधिकारिक पक्ष,स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन देना चाहें,तो उसे ससम्मान प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

बिलासपुर कलेक्ट्रेट घरने निकले कांग्रेसियों की पुलिस से झूमाझटकी कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी-बैरिकेड तोड़ा,मनरेगा बचाव संग्राम में शक्ति-प्रदर्शन

बिलासपुर, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का नाम बदलने और एक्ट बनाने के विरोध में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस ने आज बिलासपुर में प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाव संग्राम नाम से नेहरू चौक पर सभा की, फिर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव निकल गए। जिन्हें पुलिस ने स्टेट बैंक ब्रांच के पास सड़क पर बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की घेराबंदी भेदकर कांग्रेसी आगे बढ़ गए हैं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और झुमझटकी हुई। हालांकि, कलेक्ट्रेट घेरने में कांग्रेसी नाकाम रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि,मांगे पूरी नहीं होंगी तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार गांधी नाम से डरती है।

गांधी नाम से डरती है सरकार : विजय

पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि, बीजेपी सरकार गांधी के नाम से डरती है। चाहे वह महात्मा गांधी हों,राजीव गांधी हों, इंदिरा गांधी हों या राहुल गांधी हों। उन्हें रोकने की कोशिश हुई। जब जब इस देश में बीजेपी गांधी को रोकने की कोशिश करेगी,

तब तक नाथूराम गोडसे की विचारधारा नहीं चलने वाली है।

केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि,केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है। उसकी जगह नया काला कानून लागू किया गया है। इस फैसले से ग्रामीण मजदूरों को सीधा नुकसान हो रहा है। नेताओं ने मांग की कि कथित काला कानून को तत्काल हटया जाए। देश में पहले की तरह मनरेगा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि,मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका का बड़ा सहारा है।

छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवगाथा से आलोकित हुआ रायपुर: ‘जाणता राजा’ का मंचन शुरू महानाट्य ‘जाणता राजा’ के माध्यम से जीवंत हुई शिवाजी महाराज की गौरवगाथा : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 19 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है,इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खॉं के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार शाइस्ता खान के विरुद्ध उनकी युक्तिपूर्ण रणनीति यह सिखाती है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी सूझबूझ और साहस से पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ के मंचन के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री

साय ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल महान योद्धा ही नहीं,बल्कि उच्च आदर्शों वाले शासक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान किया और महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माता जीजाबाई के संस्कारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमें मर्यादा,नैतिकता और सम्मानजनक आचरण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री साय ने अपने छत्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए महाकवि भूषण की पंक्तियों का उल्लेख किया, जिनमें शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़

रहने की प्रेरणा देता है। राजधानी रायपुर में प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ का यह विशेष मंचन 22 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा।

लगभग तीन घंटे की यह भव्य प्रस्तुति छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गाथा पर आधारित है,जिसमें सजीव दृश्य, विशाल मंच सज्जा और तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से दर्शकों को ऐतिहासिक काल का जीवंत अनुभव कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस महानाट्य के लिए महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में ऑडिशन आयोजित किए गए थे,जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 40 स्थानीय कलाकारों का चयन किया गया। चर्चनित कलाकारों ने निर्देशक योगेश शिरोले के मार्गदर्शन में गहन अभ्यास किया।